कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 22 | नवंबर 16–30, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की 104वीं वर्षगांठ पर :

पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था का एकमात्र असली विकल्प समाजवाद ही है

कोरोना वायरस की महामारी और आर्थिक गतिविधियों के बार–बार बंद होने से मानव समाज, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। बेरोज़गारी, कर्ज़ और ग़रीबी, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। जब एक तरफ अधिकांश लोग अनकही पीड़ा से तबाह हैं, तब दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों ने अपनी संपत्ति पहले से कहीं ज्यादा तेज़ी से बढ़ाई है। खुद को लोकतांत्रिक कहलाने वाले राज्यों ने मेहनतकश लोगों की आजीविका और अधिकारों की सुरक्षा की बलि चढ़ाकर, अरबपति इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़े और सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सभी अनुकूल क़ानूनों को बनाया और नीतियों को अपनाया है।

मौजूदा पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था का विकल्प क्या है और इसे हक़ीक़त में कैसे हासिल किया जा सकता है – 20वीं शताब्दी ने इस प्रश्न का एक स्पष्ट उत्तर प्रदान किया है। 1917 की रूसी क्रांति और सोवियत संघ में एक समाजवादी व्यवस्था के निर्माण ने सिद्धांत और व्यवहार में ऐसे विकल्प की स्थापना की और सबके सामने पेश किया। इस प्रेरणादायक क्रांति ने दुनिया की एक–छठी आबादी को पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाई।

पेत्रोग्राद में मज़दूरों व सैनिकों के सोवियत प्रतिनिधियों की बैठक, 7 नवंबर, 1917

अक्तूबर क्रांति के बाद, सोवियत संघ में नई सामाजिक व्यवस्था, नई तरह की राज्य–सत्ता और एक नई राजनीतिक प्रक्रिया अस्तित्व में आई। यह एक ऐसी राजनीतिक ताक़त थी जो समाज को पूंजीवाद से कम्युनिज़्म (साम्यवाद) में बदलने के लिए प्रतिबद्ध थी। इससे पहले मानव समाज द्वारा हासिल की गयी, किसी भी राजनीतिक ताक़त से यह नयी राजनीतिक ताक़त, गुणात्मक रूप से अलग और श्रेष्ठ थी।

रूस में हुई अक्तूबर क्रांति, उन सभी क्रांतियों से गुणात्मक रूप से भिन्न थी, जो 19वीं शताब्दी में फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में देखी गई थीं। पहले की वे सभी क्रांतियां, बुर्जुआ–लोकतांत्रिक क्रांतियां थीं, जिनके द्वारा एक अल्पसंख्यक शोषक वर्ग के राज की जगह, दूसरे अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का राज स्थापित

शेष पृष्ठ 2 पर

1984 में सिखों के जनसंहार की 37वीं बरसी के अवसर पर विरोध प्रदर्शन

नवंबर 1984 में दिल्ली और अन्य स्थानों पर सिखों के क्रूर जनसंहार के 37 साल बाद, 1 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली के मंडी हाउस पर एक विरोध प्रदर्शन और जनसभा में 19 अलग–अलग संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शन के मुख्य बैनर पर लिखे गये नारे थे : "सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हों!" और "एक पर हमला सब पर हमला!"

इस संपूर्ण कार्यक्रम को लोक राज संगठन ने आयोजित किया था। इसमें भाग लेने वाले संगठनों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)–न्यू प्रोलतेरियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, ऑल इंडिया मजलिस–ए–मुशावरत, जमात–ए–इस्लामी हिन्द, लोक पक्ष, मज़दूर एकता कमेटी, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन, पॉपूलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (दिल्ली), पुरोगामी महिला संगठन, सिख फोरम, स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट शामिल थे।

पिछले 37 वर्षों से अधिक समय से हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने लगातार राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ राजनीतिक एकता बनाने का काम किया है। हमने उस आधिकारिक प्रचार का विरोध किया है जो सांप्रदायिक हिंसा के लिए इस या उस धर्म के तथाकथित कट्टरपंथियों को दोषी ठहराता है, इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कि यह शासक वर्ग दोषी है न कि लोगों का कोई वर्ग। हमने उन लोगों का विरोध किया है जिन्होंने दावा करते हुए आधिकारिक लाइन के साथ समझौता किया है, वह दोनों पक्ष ही दोषी हैं।

सिखों का जनसंहार हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा पूर्व–नियोजित और सबसे ऊच्च तबकों द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना और हिन्दुओं और सिखों के बीच शक पैदा करना था। इसका उद्देश्य एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवाद के सहयोग से शासक पूंजीपति वर्ग द्वारा अपनाए जा रहे ख़तरनाक रास्ते से जनता का ध्यान हटाना था। इसने राजनीतिक और आर्थिक मांगों के लिए जन–आंदोलनों के लिए बल प्रयोग को सही ठहराने का काम किया।

पिछले 37 वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि 1984 में सिखों के जनसंहार को अंजाम देने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि केंद्र सरकार के प्रभारी कई बार बदले हैं लेकिन सांप्रदायिक हत्याओं को आयोजित करने वालों में से किसी को भी सज़ा नहीं मिली है। आज अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक जनसंहारों को आयोजित करने वाले दोषी लोगों में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 1992–93 की सांप्रदायिक हिंसा, फरवरी 2002 में गुजरात जनसंहार और फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा सहित कई शामिल हैं।

सभी वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभालने वालों की आपराधिक मिलीभगत को 'दंगे' के रूप में उजागर करके पेश किया गया है। उन्होंने लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति की निंदा की। उन्होंने लोगों की एकता को बनाए रखने और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद का डटकर विरोध करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसे समाज और राज्य की स्थापना के दृष्टिकोण से सच्चाई और न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जो सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

http://hindi.cgpi.org/21570

अंदर पढ़ें

- लेनिन की पुस्तिका – 'राज्य और क्रांति' के बारे में 3
- "किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा" पर मज़दूर एकता कमेटी की बैठक 4

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की 104वीं वर्षगांठ पर :

पृष्ठ 1 का शेष

किया गया था। 1917 की अक्तूबर क्रांति ने श्रमजीवी वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग के शासन की जगह पर अब तक की शोषित जनता, बहुसंख्यक लोगों का राज स्थापित किया। श्रमजीवी वर्ग, किसानों और सैनिकों के साथ मिलकर सोवियतों में लामबंध हुये थे। जिनका नेतृत्व लेनिन की अगुवाई में एक हिरावल कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, जिसे बाद में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के रूप में जाना गया।

इस नई राजनीतिक–सत्ता और नयी राज्य–व्यवस्था को ज़िन्दा रखने के लिए और दुनिया के पूंजीपतियों की संयुक्त ताक़त के ख़िलाफ़ आगे बढ़ने के लिए नई सत्ता को बहुत बड़े और कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। दुनिया में श्रमजीवियों के सबसे पहले राज्य और समाजवादी व्यवस्था को नेस्तोनाबूद करने के लिए दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियों ने बार–बार और एक के बाद एक कई प्रयास किए। उन्होंने सशस्त्र आक्रमणों के साथ–साथ आंतरिक तोड़–फोड़ और तबाही फैलाने की कोशिशें भी कीं। दुनियाभर की साम्राज्यवादी शक्तियां कई दशकों तक चलाये गये अपने लगातार प्रयत्नों के बाद, ये शक्तियां 1956 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस से सोवियत संघ को वर्ग संघर्ष के रास्ते से हटाने में सफल हो गईं। इससे पतन की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में पूंजीवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई, जबकि समाजवाद के मुखौटे को बनाये रखा गया। इस पतन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए संकटों का फ़ायदा उठाकर, साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों ने सोवियत संघ को पूरी तरह से नष्ट करने में 1991 में सफलता पा ली।

पिछले 30 वर्षों के दौरान दुनिया के पूंजीपति इस दावे को लगातार दोहराते आ रहे हैं कि बाज़ार–उन्मुख अर्थव्यवस्था और बहुपार्टीवादी–प्रतिनिधित्वादी–लोकतंत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, जीवन के अनुभव ने बार–बार दिखाया है कि पूंजीपतियों के निजी मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लिए बनाई गयी आर्थिक व्यवस्था सभी के लिए रोज़गार और सुरक्षित आजीविका प्रदान नहीं कर सकती। एक राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें अरबपति पूंजीपतियों की प्रतिस्पर्धी पार्टियां सरकार चलाने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, यह केवल अति–अमीर अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया लोकतंत्र है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से अधिकांश लोगों को बाहर रखा जाए।

साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी ताक़तों द्वारा दुनिया के पहले समाजवादी राज्य को नष्ट किये जाने से, सोवियत अनुभव के ऐतिहासिक सबक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज जो कोई भी मौजूदा प्रणाली के विकल्प को खोजने में गंभीर रूप से रुचि रखता है, उसे आवश्यक रूप से 7 नवंबर, 2021 को पड़ने वाली 1917 की महान अक्तूबर क्रांति की 104वीं वर्षगांठ पर क्रांति के प्रेरणादायक अनुभवों और उससे जुड़ी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।

महान अक्तूबर क्रांति

फरवरी 1917 में, जब रूसी जार के शासन को बड़े पैमाने पर किये गये जन–विद्रोह के ज़रिये उखाड़ फेंका गया, तब एक असमान्य स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे लेनिन ने 'दोहरी सत्ता' कहा। एक तरफ पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अस्थायी सरकार थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को और लम्बा खींचना चाहती थी। दूसरी तरफ़ मज़दूर, किसान और सैनिक खड़े थे, जो प्रतिनिधियों की सोवियतों में संगठित थे और शांति, ज़मीन और रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे।

साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी ताक़तों द्वारा दुनिया के पहले समाजवादी राज्य को नष्ट किये जाने से, सोवियत अनुभव के ऐतिहासिक सबक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज जो कोई भी मौजूदा प्रणाली के विकल्प को खोजने में गंभीर रूप से रुचि रखता है, उसे आवश्यक रूप से महान अक्तूबर क्रांति की 104वीं वर्षगांठ पर क्रांति के प्रेरणादायक अनुभवों और उससे जुड़ी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए।

मज़दूरों के प्रतिनिधियों की सोवियत, एक विशेष शहर या कस्बे के औद्योगिक मज़दूरों के जन राजनीतिक संगठन का एक रूप थी। यह मज़दूर वर्ग के आजमाए हुए और परखे हुए प्रतिनिधियों की एक परिषद थी, जिन्हें मज़दूरों ने अपने साथियों के बीच में से खुद चुना था। 1905 में एक असफल जन–विद्रोह के दौरान मज़दूरों ने सोवियतों को जन्म दिया था। सोवियतों का विचार, एक बार फिर फरवरी 1917 में क्रांतिकारी विद्रोह के दौरान सामने आया, जिसने जार को उखाड़ फेंका। बोल्शेविक पार्टी ने देश के अधिक से अधिक भागों में सोवियतों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण के प्रयासों का नेतृत्व किया।

सोवियतों के मंचों से बोल्शेविक पार्टी ने लोगों को यह समझाया कि उनकी किसी भी ज्वलंत समस्या को मौजूदा अस्थायी बुर्जुआ सरकार द्वारा हल नहीं किया जा सकता। यह चेतना विकसित की गई कि शांति, ज़मीन और रोटी की गारंटी के लिए सोवियतों में संगठित मज़दूरों, किसानों और सैनिकों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी आवश्यक है। बोल्शेविक पार्टी के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, अक्तूबर 1917 तक सोवियतों के अधिकांश सदस्यों ने इस आह्वान का स्वागत किया कि सारी सत्ता सोवियतों के हाथों में हो!

7 नवंबर को, जो उस समय के रूसी कैलेंडर में 25 अक्तूबर की तारीख थी, क्रांतिकारी मज़दूरों, सैनिकों और नाविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया और पूंजीवादी सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार कर लिया। क्रांतिकारियों ने मंत्रालयों और स्टेट बैंक के साथ–साथ रेलवे स्टेशनों, डाक तथा टेलीग्राफ कार्यालयों पर भी कब्ज़ा कर लिया।

मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने 7 नवंबर की रात को 10 बजकर 40 मिनट पर अपनी कार्यवाही शुरू की। कांग्रेस ने मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के लिए एक अपील जारी करने को मंजूरी दी, जिसमें घोषणा की गई कि सोवियत कांग्रेस ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली है। 8 नवंबर को सोवियतों की इस कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करने के लिए शांति पर एक आदेशनामा (डिक्री) को भी मंजूरी दी। इसने भूमि पर एक आदेशनामा मंजूर किया जिसके द्वारा जमींदारों को सैकड़ों करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि से वंचित कर दिया गया और इस भूमि को किसान समितियों के हवाले कर दिया गया।

सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर सोवियत राज्य ने बड़े पूंजीपतियों की सम्पत्ति को ज़ब्त कर लिया और बड़े पैमाने के उद्योगों, परिवहन, बैंकिंग और व्यापार को सार्वजनिक स्वामित्व के तहत सामाजिक उद्यमों में बदल दिया। सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को एक ही योजना के तहत लाया गया ताकि सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

सत्ता में आने के पहले दस वर्षों के दौरान, सोवियत राज्य ने मेहनतकश किसानों को स्वेच्छा से अपनी भूमि को मिलाकर कर बड़े पैमाने पर सामूहिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। एक नई समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें न शोषण था, न बेरोज़गारी थी, न महंगाई थी और न ही किसी प्रकार का संकट था।

सोवियत राजनीतिक व्यवस्था को 'एक पार्टी की तानाशाही' का नाम देकर, पूंजीपतियों के प्रवक्ता केंद्र–बिंदु से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। केंद्र–बिंदु यह है कि पूंजीवादी देशों में लागू प्रणाली, चाहे वह मौजूदा संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली हो, दोनों में केवल एक छोटा समूह ही सभी निर्णय लेता है। जबकि सोवियत प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया में मेहनतकश बहुसंख्यक लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक नज़रिया और एक संगठित उन्नत चेतना प्रदान करती थी।

सोवियत राज्य ने महिलाओं को सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने के लिए विशेष तरीक़े अपनाए। सोवियत सत्ता ने महिलाओं और पुरुषों के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' की पद्धति की स्थापना की। सार्वजनिक कैंटीन और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को विकसित किया गया ताकि महिलाओं का भी सामाजिक उत्पादन तथा राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में पुरुषों के साथ समान स्तर पर भाग लेना संभव हो सके।

निर्णय लेने की शक्ति

पूंजीपति वर्ग और उसके सभी विचारक दावा करते हैं कि "बहुपार्टीवादी–लोकतंत्र" की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत व्यवस्था से बेहतर है जिसे वे "एक पार्टी की तानाशाही" कहते हैं। उन्होंने इस विचार को फैलाया कि एक राजनीतिक व्यवस्था की गुणवत्ता का आकलन, चुनावी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने वाली पार्टियों की संख्या से होता है।

कोई भी राजनीतिक प्रणाली लोगों के लिए लोकतंत्र की गारंटी देती है या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि उस प्रणाली में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। अमरीका, ब्रिटेन और हिन्दोस्तान जैसे पूंजीवादी राज्यों में, जो लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, निर्णय लेने की शक्ति राजनेताओं के एक छोटे समूह में केंद्रित होती है और इन राजनेताओं को सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली पूंजीपतियों द्वारा उनकी ओर से शासन करने के लिए चुना जाता है। मतदान के दिन के अलावा इस राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की और कोई भूमिका नहीं होती है और मतदान के दिन उन्हें पूंजीपति वर्ग के विश्वसनीय दलों द्वारा चुने गए एक या दूसरे उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए कहा जाता है।

सोवियत संघ में मज़दूर, सैनिक और किसान, सर्वोच्च सोवियत के सदस्यों सहित, निम्नतम से उच्चतम स्तर तक, अपनी सोवियत के लिये प्रतिनिधियों का चयन व चुनाव करते थे। चुने गए प्रतिनिधि, किसी भी समय मतदाताओं द्वारा वापस बुलाए जाने के नियम के अधीन थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों के भीतर सत्तारूढ़ और विपक्षी खेमों के बीच का कोई विभाजन नहीं था। समग्र रूप से, निर्वाचित निकाय विधायी और कार्यकारी, निर्णय लेने और सहमति से लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार थे।

जारवादी–राज्य के समय के विशेषाधिकार प्राप्त और उच्च वेतन पाने वाले नौकरशाहों के स्थान पर आम जनसेवकों को नियुक्त किया गया था, जिनके वेतन, कुशल श्रमिकों के वेतन के जैसे थे, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिया जाता था। परजीवी–जारवादी सेना की जगह एक नयी लाल सेना ने ले ली, जो शोषकों के जुल्मी राज को उखाड़ फेंकने के क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान उभरी और बढ़ी थी।

1936 में सोवियत लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। इस संविधान ने इस हक़ीक़त को स्वीकार किया कि शोषक वर्ग, सोवियत समाज में आर्थिक वर्गों के रूप में मौजूद नहीं थे। समाजवादी व्यवस्था का निर्माण एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया था, जब मज़दूरों और सहकारितावादी–किसानों के केवल दो मित्र वर्गों के अलावा बुद्धिजीवियों का भी एक तबका था।

1936 का सोवियत संविधान दुनिया का अब तक का सबसे लोकतांत्रिक और आधुनिक संविधान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित करने के अलावा, इस संविधान ने उम्मीदवारों के चयन में भी सभी मतदाताओं के अधिकारों को मान्यता दी। उस वर्ष हुए चुनावों में, उम्मीदवारों के चयन की एक लंबी और गहन प्रक्रिया भी देखी गई। सभी मतदाता, नामांकित उम्मीदवारों के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की एक निर्वाचित समिति ने इस प्रक्रिया की देख–रेख की और इसके द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों की एक

शेष पृष्ठ 5 पर

लेनिन की पुस्तिका – 'राज्य और क्रांति' के बारे में

कॉमरेड लेनिन के जन्म के 152वें वर्ष के दौरान हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में यह तीसरा लेख है। इस श्रृंखला में पहला लेख 9 मई को और दूसरा लेख 21 जून, 2021 को प्रकाशित हुआ था।

दुनिया के अधिकांश राज्य अरबपति पूंजीपतियों की एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे राज्य जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का या सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वे लोकतांत्रिक अधिकारों, मानवाधिकारों और मानव जीवन को ही कुचल रहे हैं।

साम्राज्यवाद और इजारेदार पूंजीवादी निगमों के समाज–विरोधी हमले के शिकार, मज़दूर वर्ग और अन्य सभी वर्गों व तबकों के बीच, एक सवाल बार–बार उठता है। यह सवाल है कि क्या हमारे संघर्ष का उद्देश्य सरकार चलाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी को बदलना होना चाहिए या राज्य के वर्ग स्वरूप और राजनीतिक सत्ता को बदलना होना चाहिए?

इस प्रश्न का उत्तर लेनिन ने 1917 में लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका राज्य और क्रांति में अच्छी तरह से समझाया है।

फरवरी 1917 तक, रूस और उसके कई पड़ोसी देशों के लोगों पर एक दमनकारी राजशाही का शासन था। संप्रभु ताक़त सम्राट में निहित थी, जिसे जार कहा जाता था। जार एक सैन्य नौकरशाही वाले राज्य तंत्र का नेतृत्व करता था, जो बड़े जमींदारों और बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता था। जारवादी राज्य में किसी भी सार्वभौमिक लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई थी। वह राज्य अपने क्षेत्र के मज़दूरों, किसानों, उत्पीड़ित राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं का क्रूरता से दमन करता था।

1914 में हुये अंतर–साम्राज्यवादी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जारवादी राज्य ने रूस को जर्मनी और उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ तथा ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में घसीटा। राज्य रूसी पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था, जिसके परिणामस्वरूप जारवादी सेना में सैनिक के रूप में काम करने वाले मज़दूरों, किसानों और उनके बेटों को जबरदस्त पीड़ा का सामना करना पड़ा।

फरवरी 1917 में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसने जार को उखाड़ फेंका। जारशाही निरंकुशता की जगह किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न बन गया।

एक तरफ थी पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाली अस्थायी सरकार, जो अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध में रूस की भागीदारी को लम्बा खींचना चाहती थी। दूसरी तरफ मज़दूर, किसान और सैनिक खड़े थे – जो शांति, ज़मीन और रोटी की सुनिश्चिति के प्रयास में अपनी सोवियतों में संगठित हुए थे।

कम्युनिस्ट और मज़दूर आन्दोलन के भीतर एक तीखा विचारधारात्मक संघर्ष छिड़ गया। ऐसी कई पार्टियां और समूह थे जिन्होंने तर्क दिया कि मज़दूर नेताओं द्वारा अस्थायी सरकार में भाग लेने और दबाव डालने से शांति, ज़मीन और रोटी की लोगों की मांगों को पूरा किया जा

सकता है। लेनिन ने इस तर्क को हराने के संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने इसके मार्क्सवाद–विरोधी और अवैज्ञानिक होने का पर्दाफ़ाश किया।

लेनिन ने उस निष्कर्ष का बचाव किया जिसे मार्क्स और ऐंगल्स ने 1871 के पेरिस कम्यून के अनुभव से निकाला था, वह श्रमजीवी वर्ग का राजनैतिक सत्ता पर कब्ज़ा करने का पहला प्रयास था। मार्क्स और ऐंगल्स ने यह महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्ष निकाला था कि बने बनाए बुर्जुआ राज्य व्यवस्था का इस्तेमाल करके श्रमजीवी वर्ग अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। श्रमजीवी वर्ग को बुर्जुआ राज्य से छुटकारा पाना है और एक नया राज्य स्थापित करने की ज़रूरत है जो कि श्रमजीवी वर्ग और अब तक के अन्य सभी उत्पीड़ित मेहनतकश लोगों के राज करने का एक अंग होगा।

मार्क्सवाद की इस थीसिस से मार्गदर्शित होकर, लेनिन ने तर्क दिया कि जार और उसके गुट को मंत्रियों के एक नए समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना पर्याप्त नहीं था, जो उसी जारवादी नौकरशाही, सेना, जेलों, क़ानूनों और अदालतों पर निर्भर था। सोवियतों के मंच से बोल्शेविक पार्टी ने लोगों को यह समझाया कि उनकी कोई भी ज्वलंत समस्या अस्थायी बुर्जुआ सरकार द्वारा हल नहीं की जाएगी। शांति, ज़मीन और रोटी की गारंटी के लिए, सोवियतों में संगठित मज़दूरों, किसानों और सैनिकों के लिये राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना आवश्यक है। अक्तूबर 1917 तक सोवियतों के अधिकांश सदस्य इस आह्वान के इर्द–गिर्द लामबंध हो गए थे कि : सारी सत्ता सोवियतों के हाथों में! बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, उन्होंने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया और राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

लेनिन ने मज़दूरों, किसानों और सैनिकों को यह समझाने की आवश्यकता को पहचाना कि पूंजीवाद के जुए से मुक्त करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। राज्य के सवाल पर मार्क्सवादी शिक्षाओं को विभिन्न अवसरवादियों द्वारा यूरोप और रूस में मज़दूर वर्ग के आंदोलन के भीतर विकृत किया जा रहा था। यह ज़रूरी था कि पूंजीवादी और समाजवादी राज्यों से संबंधित सभी विकृतियों और सवालों को वैज्ञानिक तरीके से तत्काल हल किया जाए। लेनिन की पुस्तिका ने क्रांतिकारी आंदोलन की इस ज्वलंत आवश्यकता को संबोधित किया।

वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने बताया था कि मानव समाज में हमेशा से राज्य नहीं था जिसमें सशस्त्र बल, जेल आदि के विशेष निकाय हों। ऐसे संस्थानों की उत्पत्ति विकास के एक विशिष्ट चरण से हुई थी, जब समाज परस्पर कट्टर विरोधी आर्थिक वर्गों में विभाजित हो गया था।

समाज के विरोधी हितों वाले वर्गों में विभाजन से पहले, सशस्त्र बल और जेलों के विशेष निकायों की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाहरी दुश्मनों से अपने खानदान या कबीले की रक्षा के लिए सभी लोग हथियारबंद होते थे। विरोधी हितों वाले वर्गों के विकास के साथ, यह असंभव हो गया था, क्योंकि सभी लोगों के हथियारबंद होने से विरोधी वर्गों के बीच हिंसक झड़पों से पूरे समाज का ही विनाश हो सकता था।

एंगेल्स द्वारा लिखे गये निम्नलिखित प्रसिद्ध गद्यांश का लेनिन ने उल्लेख किया, जिसे राज्य की सबसे प्रमाणिक मार्क्सवादी परिभाषा माना जाता है :

> "ये परस्पर विरोध, विरोधी आर्थिक हितों वाले ये वर्ग व्यर्थ के संघर्ष में अपने को और पूरे समाज को नष्ट न कर डालें, इसीलिये एक ऐसी शक्ति, जो लगे कि समाज से ऊपर खड़ी है, आवश्यक बन गयी, ताकि इस संघर्ष को हल्का किया जा सके, इसे 'व्यवस्था' की सीमा के भीतर रखा जा सके। यही शक्ति, जो समाज से उत्पन्न हुई है, लेकिन जो समाजोपरि स्थान ग्रहण कर लेती है, और समाज से अधिकाधिक पृथक होती जाती है, राज्य है।'"
>
> **(परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति)**

लेनिन ने इस बात की आलोचना की कि एंगेल्स द्वारा लिखे गए इस अंश की कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर विभिन्न अवसरवादियों द्वारा ग़लत व्याख्या की जा रही थी। उन्होंने "संघर्ष को हल्का करने" की व्याख्या, विरोधी वर्ग के हितों के साथ समझौते के रूप में की। इस ग़लत धारणा से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य वर्ग हितों के मेल–मिलाप का एक साधन है। अवसरवादियों ने इस झूठी थीसिस का इस्तेमाल बुर्जुआ अस्थायी सरकार में अपनी भागीदारी को सही ठहराने के लिए किया।

लेनिन ने बताया कि यदि विरोधी वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता, तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्य का उदय ठीक इसलिए हुआ क्योंकि विरोधी वर्गों, जैसे कि पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के हितों में सामंजस्य नहीं लाया जा सकता था। उन्होंने समझाया कि "संघर्ष को हल्का करने" का मतलब है कि उत्पीड़कों को उखाड़ फेंकने के लिए निश्चित साधनों

शेष पृष्ठ 5 पर

साम्राज्यवाद और इजारेदार पूंजीवादी निगमों के समाज–विरोधी हमले के शिकार, मज़दूर वर्ग और अन्य सभी वर्गों व तबकों के बीच, एक सवाल बार–बार उठता है। यह सवाल है कि क्या हमारे संघर्ष का उद्देश्य सरकार चलाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी को बदलना होना चाहिए या राज्य के वर्ग स्वरूप और राजनीतिक सत्ता को बदलना होना चाहिए?

इस प्रश्न का उत्तर लेनिन ने 1917 में लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका राज्य और क्रांति में अच्छी तरह से समझाया है।

मार्क्सवाद से मार्गदर्शित होकर, लेनिन ने तर्क दिया कि जार और उसके गुट को मंत्रियों के एक नए समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना पर्याप्त नहीं था, जो उसी जारवादी नौकरशाही, सेना, जेलों, क़ानूनों और अदालतों पर निर्भर था। सोवियतों के मंच से बोल्शेविक पार्टी ने लोगों को यह समझाया कि उनकी कोई भी ज्वलंत समस्या अस्थायी बुर्जुआ सरकार द्वारा हल नहीं की जाएगी। शांति, ज़मीन और रोटी की गारंटी के लिए, सोवियतों में संगठित मज़दूरों, किसानों और सैनिकों के लिये राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना आवश्यक है। अक्तूबर 1917 तक सोवियतों के अधिकांश सदस्य इस आह्वान के इर्द–गिर्द लामबंध हो गए थे कि : सारी सत्ता सोवियतों के हाथों में! बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, उन्होंने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया और राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित चौथी बैठक

किसान आंदोलन को पूरे देश में मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों का बढ़ता समर्थन मिल रहा है। संघर्ष को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है।

लगभग 500 किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एक मंच पर एक साथ आए हैं। ये मांगें हैं कि 2021 में बनाए गए तीन केंद्रीय किसान–विरोधी क़ानूनों को रद्द किया जाए, सभी कृषि फ़सलों के लिए लाभकारी एम.एस.पी. की गारंटी दी जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2021 को वापस लिया जाए और पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर किसानों को दंड देना तुरंत रोका जाए। यह इजारेदार पूंजीवादी निगमों और उनकी सेवा में लगी सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष है।

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे 11 महीने के ऐतिहासिक विरोध सहित किसानों के संघर्ष ने वर्तमान हिन्दोस्तानी लोकतंत्र के चरित्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और हमारे देश के मेहनतकश लोगों की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए समाज के मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

इन मुद्दों पर चर्चा जारी रखते हुए, 27 अक्तूबर को मज़दूर एकता कमेटी ने "किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा" विषय पर श्रृंखला की चौथी बैठक आयोजित की। बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

बैठक में मुख्य वक्ता भारतीय किसान यूनियन एकता (डकौंदा) के अध्यक्ष, बूटा सिंह बुर्ज गिल थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मज़दूर संगठनों, महिला संगठनों, युवा संगठनों, मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा में काम करने वाले संगठनों के कार्यकर्ता, सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और चर्चा में योगदान दिया।

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) की ओर से बैठक का संचालन बिरजू नायक ने किया। उन्होंने बूटा सिंह बुर्ज गिल और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, जिन्हें किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा पर अपने विचार देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

बिरजू नायक ने बताया कि बी.के.यू. एकता (डकौंदा) का गठन 2007 में पंजाब में हुआ था। उन्होंने संगठन के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि बी.के.यू. ने साहसी संघर्षों का नेतृत्व किया है और किसानों, विशेष रूप से पंजाब के ग़रीब किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को राज्य के क्रूर दमन का सामना करना पड़ा है, जिसमें गिरफ्तारियां और झूठे मुकदमे भी शामिल हैं। बूटा सिंह बुर्ज गिल के ख़िलाफ़ भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कई मामले दर्ज किए गए थे।

संगठन ने बठिंडा और मनसा में अपना काम शुरू किया, फिर संगरूर, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में फैल गया। बी.के.यू. एकता (डकौंदा) तीन किसान–विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ सामने आने वाले शुरुआती किसान संगठनों में से एक थी। यह संयुक्त

किसान मोर्चा (एस.के.एम.) का एक सक्रिय घटक है, जो वर्तमान समय में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।

सभी बाधाओं के ख़िलाफ़ संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए किसान आंदोलन की भावना को बिरजू ने दो पंक्तियों के साथ अभिव्यक्त किया, "अभी तो पांव के छाले न देखो, अभी तो यारों सफर का इब्तिदा है"। इसके बाद उन्होंने बूटा सिंह बुर्ज गिल को बैठक को संबोधित करने के लिए बुलाया।

अपने संबोधन में बूटा सिंह बुर्ज गिल ने यह दिखाने के लिए कई उदाहरण दिए कि तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग में न केवल किसानों की, बल्कि व्यापक तौर पर मज़दूरों और मेहनतकश लोगों की मांगें भी शामिल हैं। यह हिन्दोस्तानी और विदेशी बड़े इजारेदार कॉर्पोरेट घरानों की सेवा में लागू किये जा रहे निजीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ संघर्ष का हिस्सा है। बड़े–बड़े कारपोरेट घराने, जो लालची नज़रों से हिन्दोस्तान के कृषि क्षेत्र को बड़े मुनाफे के स्रोत के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने मोदी सरकार से, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए, इन केंद्रीय क़ानूनों को पारित करवाया है ताकि इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ होने वाले सभी विरोधों को दबाया जा सके। बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों किसान अपनी ज़मीन खो देंगे, राज्य में चलने वाली मंडियों में कामगारों और कृषि की लागत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अपनी आजीविका खो देंगे जब इन कार्यों पर कॉरपोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाएगा। जब किसानों को लाभकारी क़ीमतों पर राज्य द्वारा ख़रीदी से वंचित कर दिया जाएगा, तो राशन की दुकानें बंद करना मजबूरी हो जाएगी और शहरों में मज़दूरों को बाज़ार में भोजन के लिए बहुत अधिक क़ीमत चुकानी पड़ेगी।

बूटा सिंह बुर्ज गिल ने समझाया कि बिजली संशोधन विधेयक 2021, जिसको वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं, इसमें राज्य की सभी सब्सिडी को हटा दिया जायेगा, जिसकी वजह से न केवल कृषि की लागत वस्तुओं के खर्च में काफी वृद्धि होगी, बल्कि शहरों में मज़दूरों के लिए बिजली की दरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने झूठे प्रचार के माध्यम से किसान आंदोलन को बदनाम करने के साथ–साथ विभिन्न उकसावे का आयोजन करके अराजकता और हिंसा फैलाने, किसानों को विभाजित करने और उन्हें क्रूर दमन के साथ आतंकित करने के लिए, राज्य के प्रयासों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की भावना को पूरे देश में फैलाने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने आने वाले महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष को ले जाने के लिए किसान आंदोलन की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

बिरजू ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से इस विषय पर अपने विचार रखने का आह्वान किया।

एम.ई.सी. के संतोष कुमार ने बताया कि देश में सबसे बड़े इजारेदार कारपोरेट घरानों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग ही शासन कर रहा है। सरकार, इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा तय किए गए एजेंडे को लागू करने के लिए एक प्रबंधन टीम के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने समझाया कि इस प्रबंधन दल को बदला जा सकता है लेकिन इजारेदार पूंजीपतियों का एजेंडा नहीं बदलता है। संसदीय प्रणाली के साथ हमारे लोगों के अनुभव को बताते हुए, उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के बारे में भ्रम को बढ़ावा देने और लोगों को इजारेदार पूंजीपतियों के शासन के विकल्प की तलाश करने से रोकने में सत्ताधारी और विपक्षी दलों, दोनों की भूमिका को सामने रखा। इस तरह 150 से भी कम इजारेदार पूंजीपति घराने 140 करोड़ लोगों के इस देश का एजेंडा तय कर रहे हैं और हम पर राज कर रहे हैं।

संतोष ने कहा कि वास्तविक विकल्प राजनैतिक सत्ता को अपने हाथ में लेने के दृष्टिकोण से लड़ना है, ताकि हम मज़दूर और किसान समाज के लिए एजेंडा तय कर सकें, इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों द्वारा अपने लोगों की लूट को समाप्त कर सकें, और सभी मेहनतकश लोगों के लिए सुरक्षित आजीविका और प्रगति की गारंटी दे सकें।

तमिलनाडु के थनमई उलवार इयक्कम के किसान नेता, श्री गोविंदस्वामी थिरुनावुकारसु ने विस्तार से बताया कि कैसे आज़ादी के बाद से, हरित क्रांति सहित कृषि से संबंधित हिन्दोस्तानी राज्य की सभी नीतियां किसानों के हितों के ख़िलाफ़ रही हैं। हरित क्रांति ने विदेशी और हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया, कृषि के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों जैसे कृषि की लागत वस्तुओं पर इजारेदार पूंजीपतियों के वर्चस्व मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि और किसानों का विनाश हुआ। तीन कृषि कानूनों, बिजली अधिनियम, सभी किसानों के साथ–साथ मज़दूरों के भी ख़िलाफ़ हैं। वे विदेशी और हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों के फ़ायदे में हैं। हमारे देश में किसानों को उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक कभी नहीं मिला है। मज़दूरों को भी कभी नहीं मिला है। इजारेदार पूंजीवादी लालच के ख़िलाफ़ किसानों का संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है। हमारे देश के शासक वर्ग को न तो किसानों की भलाई की परवाह है और न ही मज़दूरों की भलाई की। वह किसानों को उचित एम.एस.पी. से वंचित करके उनकी आय को कम रखता है और मज़दूरों के वेतन को भी कम रखता है। हमें इस मांग को लोकप्रिय बनाना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और मज़दूरों को उचित वेतन मिले।

तमिलनाडु के एस.के.एम. के संयोजक श्री बालकृष्णन ने लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थियों को लेकर राज्य के कई कस्बों और गांवों से गुजरती हुई, आयोजित की गई यात्रा का मार्मिक विवरण दिया। बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन देने के लिए सामने आए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आंदोलन अपने संदेश को सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाने में सफल होगा।

कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.) के संयुक्त सचिव, गिरीश भावे ने किसान आंदोलन के समर्थन में मज़दूरों की एकता मजबूत करने में के.ई.सी. के काम का वर्णन किया। के.ई.सी. निजीकरण और उदारीकरण के इजारेदार पूंजीवादी एजेंडे के ख़िलाफ़ संघर्ष में, सभी प्रमुख उद्योगों और सेवाओं के मज़दूर संघों के एक आम मंच, निजीकरण के ख़िलाफ़ सर्व हिन्द मंच (ए.आई.एफ.ए.पी.) के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। किसानों का संघर्ष उसी इजारेदार पूंजीवादी एजेंडे के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि हम मज़दूरों और किसानों को, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एजेंडा तय करना होगा, न कि इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए।

ग्रेट ब्रिटेन के ग़दर इंटरनेशनल के सलविंदर ढिल्लों ने बड़े पूंजीवादी इजारेदार घरानों के एजेंडे के ख़िलाफ़ और हिन्दोस्तान में किसानों के संघर्ष के समर्थन में ब्रिटेन में लोगों को लामबंध करने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया।

लोक राज संगठन के सर्व हिंद उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने राजस्थान में किसानों के संघर्ष, सिंचाई के पानी और उनकी उपज के बेहतर मूल्य के लिए संघर्ष का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष और निजीकरण तथा बढ़ते शोषण के ख़िलाफ़ मजदूरों का संघर्ष, दोनों एक ही दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं।

समाजवादी किसान सभा के कार्यकर्ता प्रेम कुमार ने किसान आंदोलन को हमारे देश और पूरी दुनिया के उत्पीड़ित लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बताया। सिंघु बार्डर पर किसान विरोध स्थल पर मौजूद एक युवा कार्यकर्ता ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि कैसे किसान आंदोलन का संदेश विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले इतने विशाल देश के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

पुरोगामी महिला संगठन की तृप्ति ने किसान आंदोलन में और अपनी आजीविका और अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।

एक युवा कवि ने लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बर हत्या पर अपनी पीड़ा

शेष अगले पृष्ठ पर

मज़दूरों के अधिकारों पर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ सम्मेलन

11 नवम्बर को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने मज़दूरों के अधिकारों पर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ सम्मेलन किया

अक्तूबर क्रांति की 104वीं वर्षगांठ

पृष्ठ 2 का शेष

सूची तैयार की गयी। इसके बाद ही जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान हुआ।

सोवियत राजनीतिक व्यवस्था को 'एक पार्टी की तानाशाही' का नाम देकर, पूंजीपतियों के प्रवक्ता केंद्र–बिंदु से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। केंद्र–बिंदु यह है कि पूंजीवादी देशों में लागू प्रणाली, चाहे वह मौजूदा संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली हो, दोनों में केवल एक छोटा समूह ही सभी निर्णय लेता है। जबकि सोवियत प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया में मेहनतकश बहुसंख्यक लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक नज़रिया और एक संगठित उन्नत चेतना प्रदान करती थी।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद और वैज्ञानिक समाजवाद से हटने की प्रक्रिया 1956 में सोवियत पार्टी की 20वीं कांग्रेस के साथ शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर लोगों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। वहां पर निर्णय लेने की शक्ति एक संशोधनवादी गुट के हाथों में केंद्रित हो गयी जो पार्टी और राज्य का मुखिया था।

निष्कर्ष

राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की दिशा के बीच एक अविभाज्य रिश्ता है। अर्थव्यवस्था से किसे लाभ होगा और किसे नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथों में है। अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र को बदलना होगा। निर्णय लेने की शक्ति को मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों के हाथों में लाना होगा।

भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि मौजूदा संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल मज़दूरों और किसानों के हितों में किया जा सकता है। उन्होंने यह ख़तरनाक भ्रम फैलाया है कि मौजूदा राज्य को, सभी वर्गों के हितों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, हमारे मज़दूरों, किसानों और मेहनतकश जनता का दैनिक अनुभव, इस लेनिनवादी निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि संसदीय लोकतंत्र, पूंजीपति वर्ग की तानाशाही का एक रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन–सी पार्टी सरकार बनाती है और कौन–सा व्यक्ति मंत्री बनता है, पूंजीपति वर्ग का राज हर हालत में सुरक्षित बना रहता है।

आज हमारे देश में पूंजीवादी हमले के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों का संघर्ष उफान पर है। वक़्त की मांग है कि पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी राज्य सत्ता के ख़िलाफ़, सभी कम्युनिस्ट मिलकर मज़दूर वर्ग, किसानों और सभी उत्पीड़ित वर्गों की राजनीतिक एकता को बनाने और मज़बूत करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं जैसा कि बोल्शेविकों ने अपने समय में किया था। पूंजीवादी हमले के ख़िलाफ़ संघर्ष, मेहनतकश जनता को सशक्त बनाने और मौजूदा अर्थव्यवस्था, जो केवल अति–अमीर शोषकों के अल्पसंख्यक वर्ग की हवस और लालच को पूरा करने के लिए बनाई गयी है, उसकी दिशा बदलकर आम मेहनतकश जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उसको नयी दिशा देने के लिए है।

http://hindi.cgpi.org/21564

लेनिन की पुस्तिका – 'राज्य और क्रांति' के बारे में

पृष्ठ 3 का शेष

और संघर्ष के तरीक़ों से उत्पीड़ित वर्गों को वंचित करना है। उद्धरण चिन्हों के भीतर 'व्यवस्था' का मतलब है बुर्जुआ वर्ग की निर्विवाद तानाशाही।

लेनिन ने एंगेल्स की थीसिस के सार को विस्तार से बताया, कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है। यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का एक साधन है। आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग इस उपकरण के ज़रिये राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग बन जाता है।

यूरोप में राज्य के विकास के इतिहास को देखते हुए, लेनिन ने समझाया कि दास समाज में, राज्य ने दासों के मालिकों के हितों की रक्षा की और दासों को विद्रोह करने से बलपूर्वक रोका। सामंतवाद की अवस्था में राज्य ने कुलीन वंश के बड़े जमींदारों के हितों की रक्षा की। पूंजीवाद के विकास के साथ, पूंजीपति वर्ग ने राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया और इसे अपने हितों के अनुरूप ढाला।

पूंजीपति वर्ग ने अपने शासन के अंग को और अधिक परिष्कृत किया है। एक राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें प्रतिस्पर्धी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक न्यायपालिका जिसे सरकार से स्वतंत्र माना जाता है, इनको राज्य के वर्ग चरित्र को छिपाने के लिए विकसित किया गया है। वे इस गलत धारणा को बनाने का काम करते हैं कि राज्य वर्गों और वर्ग हितों से ऊपर है।

श्रमजीवी वर्ग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुर्जुआ राज्य का उपयोग नहीं कर सकता। यह निष्कर्ष प्रश्न उठाता है कि – श्रमजीवी वर्ग को किस प्रकार के राज्य की आवश्यकता है?

लेनिन ने एंगेल्स की थीसिस के सार को विस्तार से बताया, कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है। यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का एक साधन है। आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग इस उपकरण के ज़रिये राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग बन जाता है।

लेनिन ने पेरिस कम्यून के अनुभव के अध्ययन पर आधारित राज्य के मार्क्सवादी विश्लेषण के विकास को देखा। सर्वहारा वर्ग द्वारा अपना शासन स्थापित करने का पहला प्रयास पेरिस कम्यून था। भले ही पेरिस के मज़दूर कुछ हफ्तों से अधिक समय तक सत्ता पर काबिज़ नहीं रह सके, इस क्रांतिकारी अनुभव से मार्क्स और एंगेल्स ने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्ष निकाले थे।

पेरिस कम्यून का पहला फ़रमान स्थायी सेना का दमन और उसके स्थान पर सशस्त्र लोगों को रखना था। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में राज्य के अधिकारियों के लिए सभी मौद्रिक विशेषाधिकारों का ख़ात्मा और उनके पारिश्रमिक को "मज़दूरों के वेतन" के स्तर तक कम करना शामिल था। कम्यून एक कार्यकारी निकाय था और बुर्जुआ संसद की तरह बातचीत की दुकान नहीं था। विधायी और कार्यकारी शक्तियों में कोई विभाजन नहीं था। कानून और नीतियां बनाने वाले उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए भी ज़िम्मेदार थे। सत्तारूढ़ और विपक्षी खेमों के बीच कोई विभाजन नहीं था। पूरा निर्वाचित निकाय उन लोगों के प्रति ज़िम्मेदार और जवाबदेह था जिन्होंने उन्हें चुना था।

राज्य पर मार्क्सवादी शिक्षाओं का साहसपूर्वक बचाव और दृढ़ता से समर्थन करते हुए, लेनिन के साथ बोल्शेविक पार्टी ने अन्य सभी मेहनतकश लोगों के साथ गठबंधन में श्रमजीवी वर्ग के शासन के अंग के रूप में सोवियत राज्य को बनाया और समेकित किया। जारवादी सेना को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पर लाल सेना को स्थापित किया गया। विशेषाधिकार प्राप्त नौकरशाही को हटाकर प्रशासकों, लेखाकारों और तकनीशियनों को सोवियतों के नियंत्रण में लाया गया।

यह पुस्तिका भले ही 100 साल से अधिक पुरानी है, लेकिन राज्य और क्रांति पर लेनिन की पुस्तिका की प्रासंगिकता बरकरार है। यह अमानवीय पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था को खत्म करने और मानव समाज के लिए सभ्यता के उच्च पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग खोलने के संघर्ष में लगे सभी लोगों के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री का हिस्सा है।

http://hindi.cgpi.org/21556

किसान आंदोलन पर बैठक

पृष्ठ 4 का शेष

व्यक्त करते हुए, एक स्व–रचित कविता का पाठ किया जिसमें उन्होंने कसम खाई कि लोग उत्पीड़कों के अपराधों को कभी माफ़ नहीं करेंगे।

बूटा सिंह बुर्ज गिल ने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने समझाया कि एम.एस.पी. और राज्य द्वारा ख़रीद की गारंटी की मांग एक ऐसी मांग है, जो इजारेदार पूंजीवादी एजेंडे पर सीधा वार करती है। उन्होंने कहा कि – हमारी मांग है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए और मज़दूरों को उचित मज़दूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि किसान आंदोलन को देश के कोने–कोने से समर्थन मिलने से विभिन्न भाषाओं में लोगों तक संदेश पहुंचाने की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आगे आने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प और आंदोलन की एकता में उनके अपार योगदान की सराहना की। उन्होंने एक लोकप्रिय दोहे के प्रेरक शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त किया – "हाकीम हारते हैं, लोग नहीं"।

बिरजू नायक ने इन आशावादी बातों के साथ बैठक को निष्कर्ष पर पहुंचाया कि वह दिन दूर नहीं, जब एक नया हिन्दोस्तान होगा, जिसमें सबके लिये सुख और सुरक्षा की गारंटी होगी।

http://hindi.cgpi.org/21568

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Nov, 2021 Date of publish - 16 Nov, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21ए, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शहादरा, दिल्ली से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020। email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

नोटबंदी के पांच साल बाद :

नोटबंदी के असली इरादे और झूठे वायदे अब स्पष्ट हो गए

8 नवंबर, 2016 को जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, उसके पांच साल बाद, उसे जायज़ ठहराने के लिए जो झूठे वायदे किये गए थे, उनका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। नोटबंदी को लागू करने के असली इरादे भी अब साफ हो गए हैं।

प्रचलित रुपयों का 86 प्रतिशत, यानी सभी 500 और 10,00 रुपए के नोटों को, 8 नवंबर, 2016 की आधी रात से अवैध घोषित कर दिया गया। लोगों को बैंकों में अपने पुराने नोटों को जमा करने के लिए मात्र 50 दिन दिए गए।

बैंक से कितना पैसा निकाला जा सकता था, उस पर कड़ी सीमाएं लगाई गयीं। 2,000 रुपये के नए नोट और दूसरे नए नोट कुछ समय के बाद ही जारी हुए। काफी समय तक नगदी पैसे की बहुत कमी थी। लोगों को बैंकों में अपने नोट जमा करने के लिए या ज़रूरी काम के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा निकालने के लिए, कई दिनों तक लगातार, लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। एटीएम में नोट ख़त्म हो गए। बैंक कर्मचारियों को लंबे–लंबे घंटों तक काम करना पड़ा और अक्सर लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी को धन की बढ़ती असमानता के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के ख़िलाफ़, एक जिहाद के रूप में जायज़ ठहराया था। उन्होंने दावा किया था कि नोटबंदी का मक़सद है भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा किए गए काले धन को बाहर निकालना और उसे ग़रीब मेहनतकश लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करना। उन्होंने दावा किया था कि नोटबंदी का उद्देश्य है उन जाली नोटों को ख़त्म करना जिनके सहारे विदेशी ताक़तें हिन्दोस्तान में आतंकवाद को प्रश्रय देती हैं।

लाखों–लाखों दिहाड़ी मज़दूर और ठेका मज़दूर काम से निकाल दिए गए, क्योंकि उनके मालिकों के पास उन्हें वेतन देने के लिए नगद पैसे नहीं थे। छोटे और मध्यम उद्योग, थोक और खुदरा व्यापार, पर्यटन, यातायात, निर्माण और बहुत–सी ऐसी दूसरी गतिविधियां जो मुख्यतः नकद पैसे से चलती थीं, उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ। कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। देश के कई इलाकों में किसानों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि रबी फ़सल के समय पर, आवश्यक कृषि सामग्रियां खरीदने के लिए उनके पास नकद पैसे नहीं थे। जिस समाज में अधिकतम लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए हमेशा नगद पैसों पर निर्भर होते हैं, ऐसे समाज में नोटबंदी का फौरी आर्थिक असर सचमुच विनाशकारी साबित हुआ।

परंतु हिन्दोस्तान के सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों – टाटा, अंबानी, बिरला, आदि ने नोटबंदी का स्वागत किया। छोटे और मध्यम उद्योगों और सेवाओं का विनाश तथा किसानों की तबाही इजारेदार पूंजीवादी घरानों के लिए, अपने साम्राज्यों का विस्तार करने और अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मौका साबित हुआ। लोगों को रातों–रात नगद पैसे से वंचित करना, यह उन्हें लाखों–लाखों लोगों को जबरदस्ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को जल्दी से अपनाने को मजबूर करने और इस प्रकार बेशुमार मुनाफ़े कमाने का सबसे अच्छा रास्ता नज़र आया। 8 नवंबर, 2016 के बस कुछ ही दिनों के अंदर सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों ने फटाफट अपने–अपने डिजिटल पेमेंट बैंक स्थापित कर लिए, जिनके ज़रिए वे बेशुमार मुनाफ़े कमाते आ रहे हैं।

2016 से पूरे देश में बहुत सारी डिजिटल पेमेंट कंपनियां और पेमेंट बैंक चालू हो गए हैं। लोगों को बैंकिंग, बीमा, थोक और खुदरा व्यापार, खाद्य, वस्त्र, घरेलू सामान, दवाइयां, किताबें, आदि ढेर सारी चीजों के लिए तथा डॉक्टरी सलाह, शिक्षा और बहुत सारी ज़रूरी सेवाओं के लिए, डिजिटल लेनदेन करने को मजबूर कर दिया गया है।

बीते 5 वर्षों ने यह साबित कर दिया है कि नोटबंदी "वित्त क्षेत्र के सुधारों" के उस एजेंडा को लागू करने का एक साधन था, जिसे सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति बढ़ावा दे रहे थे। लोगों को अपनी बचत के सारे पैसे को बैंकों में जमा करने को मजबूर करके और नगदी से हटकर डिजिटल लेनदेन करने को मजबूर करके, इजारेदार वित्त पूंजी के लिए, लोगों को और सक्रियता से तथा और विस्तृत रूप से लूटना ज्यादा आसान हो गया।

5 साल बाद, नोटबंदी और उसके बाद जी.एस.टी., के लंबे दौर के असर बढ़ती बेरोज़गारी और अमीरों तथा ग़रीबों के बीच में बढ़ती खाई के रूप में देखे जा सकते हैं। आर्थिक संवर्धन में मंदी 2020 के कोविड–19 संकट से पहले ही नज़र आ रही थी। यह स्पष्ट है कि जबकि नोटबंदी की वजह से, एक तरफ मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकश लोगों के दुख–दर्द बहुत बढ़ गए, तो दूसरी तरफ, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों को अपनी दौलत को बड़ी तेज़ी से बढ़ाने का मौका मिला।

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने का दावा आज एक बहुत बड़ा झूठ साबित हो चुका है।

भ्रष्टाचार, जो कि राज्य और सरकार के उच्चतम स्तरों से शुरू होता है, वह आज कई गुना बढ़ गया है तथा और स्पष्ट होने लगा है। बड़े–बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों से लाखों–करोड़ों रुपयों के कर्ज़े ले रखे हैं, जिन्हें चुकाने से इंकार कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इन कर्ज़ों को माफ़ करने का आदेश दिया जा रहा है। यह हमारे समय के सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांडों में से एक है और जनता के धन की अपराधी लूट है। इसमें उधार लेने वाले बड़े–बड़े पूंजीपतियों, बैंकों और वित्त संस्थानों के प्रधानों तथा राज्य के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों के बीच की सांठगांठ भी साफ–साफ नज़र आती है।

सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़ों को तेज़ी से बढ़ाने के मक़सद से, "मुद्रीकरण" के नाम से, लाखों–करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति की लूट, रेलवे, टेलिकॉम, बिजली, रक्षा, आदि जैसे अहम सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की निजी पूंजीपतियों के हाथों खुलेआम बिक्री, एयर इंडिया का कौड़ियों के दाम पर टाटा समूह को बेचा जाना – ये सब संस्थागत भ्रष्टाचार और जनता की लूट हैं, जिनके लिए राज्य के उच्चतम स्तरों द्वारा सहूलियतें दी जाती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि 29 अगस्त, 2018 तक उसे नवंबर 2016 में प्रचलित नोटों का 99.3 प्रतिशत वापस मिल चुका था। इससे यह दावा, कि नोटबंदी के ज़रिए करोड़ों–करोड़ों बेहिसाब जाली नोट जब्त होंगे, सरासर झूठ साबित हो गया है।

नोटबंदी की घोषणा करने के समय सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें नगदी के रूप में लगभग 4–5 लाख करोड़ रुपए का बेहिसाब काला धन जब्त करने की उम्मीद थी। परंतु जाना जाता है कि बीते 5 वर्षों में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां ही जब्त की गयी हैं।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इतना सारा काला धन जब्त किया जाएगा कि हर ग़रीब व्यक्ति के बैंक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ! विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन को वापस लाने का दावा भी आज पूरी तरह झूठा साबित हो चुका है।

आज भी सैकड़ों लोग आतंकवाद का शिकार बनते रहते हैं। आतंकवाद को प्रश्रय देना हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग के हित में है क्योंकि हुक्मरान वर्ग आतंकवाद को बहाना बनाकर, लोगों पर दमन और राजकीय आतंकवाद के प्रयोग को जायज़ ठहरा सकते हैं। दुनिया में आतंकवाद का सरगना, अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ हिन्दोस्तानी राज्य का रणनीतिक गठबंधन है। इसके अलावा दुनिया में आतंकवाद फैलाने वालों के पास पैसों की लेनदेन करने के बहुत सारे आधुनिक तौर–तरीके हैं; उन्हें जाली नोटों की कोई ज़रूरत नहीं होती है।

5 साल बाद, यह बहुत साफ हो गया है कि नोटबंदी से अमीरों और ग़रीबों के बीच की खाई बिलकुल कम नहीं हुई है। न तो भ्रष्टाचार कम हुआ है और न ही आतंकवाद। 2016 में सरकार ने नोटबंदी को जायज़ ठहराने के लिए जो–जो दावे किए थे, उनमें से हर एक आज झूठा साबित हो चुका है। आज यह स्पष्ट है कि नोटबंदी देश के मज़दूरों, किसानों और जन समुदाय को लूटकर, देशी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों की दौलत को बढ़ाने के एक और तरीक़े के सिवाय, कुछ और नहीं था।

http://hindi.cgpi.org/21547

नोटबंदी के असली इरादे और झूठे दावे

(प्रथम प्रकाशन जनवरी 2017)

इस पुस्तिका के प्रथम भाग में नोटबंदी के असली इरादों को समझाने तथा उनका पर्दाफाश करने के लिये, तथ्यों और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में सरकार के दावों – कि नोटबंदी से अमीर–गरीब की असमानता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद ख़त्म होगा – का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। तीसरे भाग में यह बताया गया है कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अनुसार, इन समस्याओं का असली समाधान क्या है तथा उस समाधान को हासिल करने के लिये फौरी कार्यक्रम क्या होना चाहिये।

Mazdoor Ekta Lehar (Internet Editions)

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org, English: http://www.cgpi.org

Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org & Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com

Ph.09868811998, 09810167911